THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) to (d). The procurement prices fixed by the Government operate as support prices and the producers are free to sell their produce in the market at higher prices. Thus, there can be some difference between the procurement price and the market price. The F.C.I. and other procuring agencies have been advised to make necessary arrangements for purchasing foodgrains at the procurement prices wherever necessary to avoid distress sale by farmers at prices below their economic levels. Quantitative limits on holding of stocks of foodgrains have been fixed by the State Governments, wherever necessary to prevent hoarding.

Working days recovery and Actual Price paid for Sugarcane

2553. SHRI M. R. LAKSHMINARAYANAN: Will the Minister of AGRICUTURE AND IRRIGATION be pleased to state crushing capacity, number of working days, total sugar produced, statutory minimum price and the actual price paid per ton of sugarcane including any incentives and subsidies given by the sugar factories for the season 1974-75, State-wise and factory-wise?

THE MNISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): Three statements giving the required information are laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-10703/76.]

मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसियां

2554. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसियां किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है;

(ख) क्या इन एजेंसियों के कृत्यों का विस्तार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इन एजेंसियों द्वारा कृषकों तथा श्रमिकों को दिए गए ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर में कमी करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी कार्यक्रम मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

1. दुर्ग
*2. रायसेन-सेहोर
3. बिलासपुर
4. छिंदवाड़ा
**5. रतलाम
6. शाहडोल
7. सागर
8. जबलपुर
9. सतना
10. मंदसौर
11. राजनन्दगांव
12. सरगुजा

---

*रायसेन-सेहोर जिलों में इस कार्यक्रम को एक विशेष मामले के रूप में वर्ष 1976-77 के अन्त तक और एक वर्ष के लिए जारी रखा जा रहा है । उसके बाद, यह कार्यक्रम छतरपुर जिले में आरम्भ किया जाएगा ।

**1-4-1976 से यह कार्यक्रम रतलाम जिले के लिए सीमित किया जाना है लेकिन एजेंसी को उज्जैन जिले मे चालू वर्ष में 1975-76 से बची हुई गतिविधियों को पूरा करने की अनुमति दी गई है । तथापि एजेंसी द्वारा उज्जैन जिले में 1-4-76 के बाद कोई नई योजना आरम्भ नहीं की जाएगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ये एजेंसिया लघु किसानों/सीमांत किसानों तथा कृषि श्रमिकों को सहकारी सोसायटियों के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु अंश पूजी के लिए ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर कोई ऋण नहीं देती है । विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए ऋण सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाते है । वित्तदायी संस्थाओं द्वारा लाभभोगियों को दिए गये ऋणों पर ब्याज की दर को घटाने का कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

मध्य प्रदेश में चम्बल नहर द्वारा सिंचित भूमि

2255. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल नहर द्वारा मध्य प्रदेश के मुरेना एवं भिंड जिलों की कितनी भूमि की सिंचाई की जानी है ;

(ख) क्या चम्बल नहर की बहुत सी उप-नहरें अभी भी जल के बिना खाली है और यदि हां, तो ऐसी उप नहरों की संख्या क्या है और उनकी लम्बाई कितनी है; और

(ग) इन नहरों को कब तक पूरा पानी मिलने लगेगा तथा इनसे कितनी भूमि की सिंचाई होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मोरेना और भिण्ड जिलों में चम्बल नहर द्वारा क्रमश: 19216 और 153947 हैक्टेयर क्षेत्रों की सिंचाई होती है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि अम्बाह, मोरेना एवं भिण्ड नहर शाखाओ की अन्तिम छोरों में 38.74 किलोमीटर की लम्बाई में 16 उपनहरों को पानी नहीं मिल रहा है जिससे 3441 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है । इन क्षेत्रों को 1980 तक पानी मिलेगा जबकि सभी नहर क्षेत्र विकासात्मक कार्य पूर्ण हो जाएंगे ।

मध्य प्रदेश में 1974-75 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन और उसकी वसूली

2256. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ; और

(ख) इस अवधि में कुल कितनी मात्रा में गेहूं तथा चावल की वसूली की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :